

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक

21, अगस्त, 2015:

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-30 आयोजनागत (एस0सी0एस0पी0) पक्ष में महिला डेरी विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-447/लेखा-प्रस्ताव आयो0 महिला डेरी/2015-16, दिनांक 23 जुलाई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संख्या-645/ XX VII(1)/2015, दिनांक 04 जून, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में महिला डेरी विकास योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत रु० 30.00 लाख (रुपये तीस लाख मात्र) निम्नलिखित मदों में धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	मद का नाम)	(धनराशि रुपये लाख में)
		स्वीकृति धनराशि
1.	महिला दुग्ध समितियों का गठन	
2.	एस.सी.एस.पी. सदस्यों को चैफकटर वितरण का अनुदान	2.70
2.	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	7.10
3.	प्रपोलसन चार्ज	15.00
4.	एक्सटेंशन एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	1.91
5.	ओवरराईडिंग कॉस्ट	1.38
		1.91
	योग-	30.00

- सुपरवीजन, मॉनीटरिंग मद की धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य महिला समितियों पर समितियों के पर्यवेक्षण अथवा कार्यालय में कार्यरत अनुसूचित जाति के कार्मिकों के वेतन-भत्ते का भुगतान पर व्यय नहीं की जायेगी यदि जाति बाहुल्य समितियों के पर्यवेक्षण एवं कार्यालय की पृथक से व्यवस्था की गई है तब ऐसे पर्यवेक्षण एवं कार्यालय में लगे कार्मिकों के वेतन-भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रप्लसन चार्ज, ओवरराईडिंग कास्ट एवं एक्सटेंशन एवं ट्रेनिंग कार्यक्रम मदों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि पर उक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- उक्त स्वीकृति जनपदवार सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्ट करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
 4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
 5. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
 6. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- 2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनाएं-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-0202-महिला डेरी विकास योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-36(P)/XXVII-4/2015, दिनांक 14 अगस्त, 2015 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
(डॉ० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-386-(1)/XV-2/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग-4, /नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।